भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या2782

जिसका उत्तर 20दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है।

29 अग्रहायण, 1945 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार

2782. श्री संजय सेठ:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की पंजाब सहित अनुमानित लागत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ग) क्या यह कार्यक्रम आईटी पेशेवरों के कौशल के विस्तार और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एमएसएमई के डिजिटल लॉकर एप का भी विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के माध्यम से लोगों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न सरकारी सेवाएं और सुविधाएं कौन-सी हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश के प्रत्येक हिस्से में डिजिटल प्रिंट को व्यापक रूप से सुधारने और विस्तारित करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): जीहाँ।

(ख): सरकारनेडिजिटलपहुंच, डिजिटलसमावेशन, डिजिटलसशक्तिकरणऔरडिजिटलविभाजनकोपाटकरभारतकोडिजिटलरूपसेसशक्तसमाजऔरज्ञानआधारितअर्थव्यवस्थामेंबदलनेकीदृष्टिसेडिजिटलइंडियाकार्यक्रमशुरूकियाहै।कार्यक्रमतीनप्रमुखदृष्टिक्षेत्रोंपरकेंद्रितहै, अर्थात्प्रत्येकनागरिककेलिएमुख्यउपयोगिताकेरूपमेंडिजिटलअवसंरचना, मांगपरशासनऔरसेवाएं, औरनागरिकोंकाडिजिटलसशक्तिकरण।समग्रलक्ष्ययहसुनिश्चितकरनाहैकिडिजिटलप्रौद्योगिकियांप्रत्येकनागरिककेजीवनमेंसुधारकरें, भारतकीडिजिटलअर्थव्यवस्थाकाविस्तारकरेंऔरनिवेशऔररोजगारकेअवसरपैदाकरें।डिजिटलइंडियानेसरकारऔरनागरिकोंकेबीचकीदूरीकोकाफीहदतककमकरदियाहैऔरसरकारऔरशासनपरविश्वासबढ़ायाहै।इससेपारदर्शीऔरभ्रष्टाचारमुक्ततरीकेसेसीधेलाभार्थियोंतकसेवाएंपहुंचानेमेंभीमददमिलीहै।इसप्रक्रियामें, भारतअपनेनागरिकोंकेजीवनकोबदलनेकेलिएप्रौद्योगिकीकाउपयोगकरनेवालेदुनियाकेप्रमुखदेशोंमेंसेएककेरूपमेंउभराहै।

अगस्त 2023 में, सरकारने 15वेंवित्तआयोगअर्थात 2021-22 से 2025-26 कीअवधिकेदौरान₹14,903.25 करोड़केकुलपरिव्ययकेसाथडिजिटलइंडियाकार्यक्रमकेविस्तार/प्रसारकोस्वीकृति दी।डिजिटलइंडियाकार्यक्रमकेअंतर्गत 8 उप-योजनाएँहैं।परिव्ययसहितयोजनाओंकाविवरणसंलग्नहै।येउप-योजनाएँकेंद्रीयक्षेत्रकीयोजनाएँहैं, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश-वार आवंटन नहीं किया जाता है।

(ग): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना में रोजगार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति के पुन: कौशल/उन्नयन के लिए भावी कौशल प्राइम कार्यक्रम शामिल है जिसे भविष्य के लिए तैयार और उद्योग के लिए तैयार प्रौद्योगिकियों से निपटने वाले उद्योग के साथ भागीदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार, सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यक्रमसूचनासुरक्षाकेक्षेत्रमेंमानवसंसाधनपैदाकरनेऔरविभिन्नहितधारकोंकोकवरकरतेहुएराष्ट्रीयस्तरपर जनजागरूकतापैदाकरनेकेलिएहै।

(घ): डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म को एमईआईटीवाई द्वारा निवासियों को डिजिटल रूप से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिए क्लाउड-आधारित मंच के रूप में शुरू किया गया है। डिजीलॉकर सेवा को एमएसएमई उद्यमों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, संगठनों और अन्य गैर-व्यक्तिगत एजेंसियों के लिए एंटिटी लॉकर के रूप में विस्तारित किया जा रहा है, ताकि सुरक्षित और पेपरलेस तरीके से महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों की आसान पहुंच और सत्यापन किया जा सके, जिससे दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

(ङ): डिजिटलइंडियाकार्यक्रमकेप्रसार/विस्तारकेमुख्यलाभनिम्नानुसारहैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक्सऔरआईटीउद्योगकेविनिर्माणऔरसेवाक्षेत्रोंकेलिएप्रशिक्षितमानवसंसाधनोंकीउपलब्धतासुनिश्चितकरना।

(ii) डिजिटलसार्वजनिकअवसंरचना/प्लेटफार्मोंऔरडिजिटलसमावेशनकेमाध्यमसेनागरिकोंकोडिजिटलरूपसेसशक्तबनाना।

(iii) शैक्षणिकऔरअनुसंधानसंस्थानोंऔरसरकारीसंस्थानोंकोउच्चगतिकनेक्टिविटीप्रदानकरना।

(iv) इलेक्ट्रॉनिक्सऔरआईटीहार्डवेयरमेंविनिर्माणक्षमताओंऔरआत्मनिर्भरताकेविकासकोबढ़ावादेना।

(v) आईटीक्षेत्रमेंभारतकीताकत,
विघटनकारीनवाचारोंऔरअत्याधुनिकप्रौद्योगिकीकालाभउठातेहुएएकस्थायीसॉफ्टवेयरउद्योगकेनिर्माणकोबढ़ावादेना।

(vi) सुपरकंप्यूटिंग, क्वांटमटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेनऔरआर्टिफिशियलइंटेलिजेंसआदिसहितमुख्यऔरव्यावहारिकक्षेत्रोंमेंअनुसंधानकोबढ़ावादेना।

(vii) देशमेंसाइबरसुरक्षाकोबढ़ानेकेलिएराष्ट्रीयस्तरपरवास्तविकसमयमेंसाइबरसुरक्षास्थितिजन्यजागरूकतापैदाकरना।

(viii) डिजिटलभुगतानकोबढ़ावादेनाऔरलेनदेनमेंपारदर्शितालाना।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ प्रमुख सुविधाओं में आधार (डिजिटल पहचान), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (डिजिटल भुगतान), डिजीलॉकर (पेपरलेस गवर्नेंस), उमंग (मोबाइल गवर्नेंस), एपीआई सेतु (डेटा एक्सचेंज), कोविन (टीकाकरण मंच), सरकारी ई-मार्केट प्लेस (सार्वजनिक खरीद), दीक्षा (डिजिटल शिक्षा), ई-संजीवनी (डिजिटल हेल्थकेयर) आदि शामिल हैं।

(च): डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के अलावा, सरकार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0, इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस), इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2.0, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब विनिर्माण आदि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास सहित भारत अर्धचालक मिशन के माध्यम से उत्पादन, रोजगार बढ़ाने और आत्म निर्भरता को बढ़ावा देने के लिए

विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) नए केंद्र/विस्तार केंद्र खोलकर कौशल/पुन: कौशल के दायरे का विस्तार करेगा। इन पहलों से डिजिटल पदचिह्न में सुधार होगा और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के आकार का विस्तार होगा।

******

अनुबंध

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमोदित परिव्यय का योजना-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**उप-योजनाकानाम**	**अनुमोदितपरिव्यय 5 वर्षोंकेलिए (₹करोड़में)**
1.	क्षमतानिर्माणएवंकौशलविकास	2,858.00
2.	इलेक्ट्रॉनिकगवर्नेंस	2,328.27
3.	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन)	1,645.52
4.	इलेक्ट्रॉनिक्सऔरआईटीहार्डवेयरविनिर्माणकोबढ़ावादेना	628.10
5.	आईटीऔरआईटीईएसउद्योगोंकोबढ़ावादेना	828.00
6.	आईटी ,इलेक्ट्रॉनिक्सऔरकन्वर्जेंस , संचारऔरब्रॉडबैंडटेक्नोलॉजीजमेंअनुसंधानएवंविकास	4,431.46
7.	साइबर सुरक्षा परियोजनाएँ (राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और अन्य)	2,034.00
8.	डिजिटलभुगतानकोबढ़ावा#	149.90
	कुलपरिव्यय:	14,903.25

- योजनादिनांक 17.07.2023सेवित्तीयसेवाविभाग (डीएफएस), वित्तमंत्रालयकोहस्तांतरितकरदीगई।

****